

Form -1
(For Linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Dehradun

No: DDN/2021 Dated: 23-12-2021

No. 263 /DLRC/ 2022

DATE:- 30/3/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEf), Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009, Wherein the MoEf issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEfs letter dated 5th February 2013 wherein MoEf issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **0.144 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of M/s BSNL Dehradun for Lay of Optical Fiber Cable in Dehradun District.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA is exempted for the entire **0.144 Hectares** of forest proposed for diversion in case of linear projects.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA is exempted in case of Linear project.
- c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre agricultural communities.
- d) This certificate is being issued on the basis of the report of Divisional Forest Officer Kalsi of Land Conservator of Forest Division, Kalsi.

District Magistrate

जिल्हा निकारा
Dehradun
उत्तराखण्ड

परियोजना का नाम :- रा०ट्रीप अ०टेक्टल फॉइबर लैटरके
 (भारत सरकार की एक परियोजना हाम पंचायतों का वाकांड)
 कॉनोकेटविटी पुदान करजे के लिए है) कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर

उपखण्ड विकासनगर परिषेक के अन्तर्गत दलानी हाम पंचायत
 (0.144 है) आरक्षित वन भूमि, — है) सिविल एवं सोयम वन भूमि - है) का
 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल है) वन भूमि) का
0.144 है प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 17/02/2022 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
 श्री विनाइ कुशार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
 अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में भाननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

अध्यक्ष	उपजिलाधिकारी	विकासनगर	सदस्य
श्री <u>पिंगुट कुशार</u>	उपजिलाधिकारी	सरमुख (<u>राज.पर</u>)	सदस्य
श्री <u>विनाइ कुशार</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>राज.पर</u> (<u>राज.पर</u>)	सदस्य
श्रीमति <u>पूजा पाल</u>	सहायक समाज सेवा विभाग अधिकारी	<u>राजनावली</u> (<u>राज.पर</u>)	सदस्य/सचिव
श्रीमति <u>संजय बिहारी</u>	वी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य क्षेत्र पंचायत	विकासखण्ड	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि २०८८ परियोजना अन्तर्गत फॉइबर लैटरक (राज. और एक राज.) (भारत सरकार की एक परियोजना हाम पंचायतों का बाउबॉड कॉनोकेटविटी पुदान भूमि के लिए है) परियोजना हेतु 0.144 है) वन

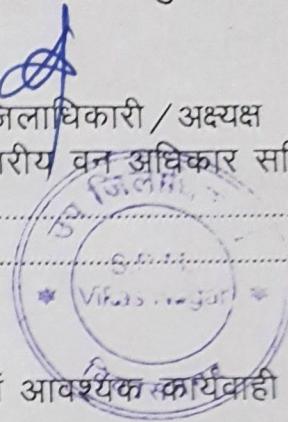
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री की०डी०विकासनगर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधिक नियमों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

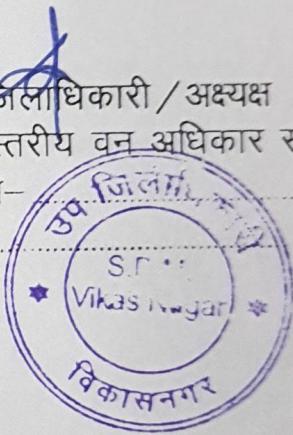
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकासनगर परिषेक के अन्तर्गत
सुन औ एफ.एन (NDFN) परियोजना के निर्माण हेतु 0.144
हेठले वन भूमि B.S.N. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—



प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, डॉ. इंद्रा इन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक स्वार्थीकरण हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय उंचिकल पाइवर नेटवर्क

(भारत सरकार की एक परियोजना, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ठलानी
तहसील विकासनगर जिला दहरादून

दहरादून, विकासनगर अनापति प्रमाण पत्र स्न जो एक स्न परियोजना उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत स्न जो एक स्न परियोजना के निर्माण हेतु (0.144 हेतु आरक्षित वन भूमि, —— हेतु सिविल सोयम भूमि— हेतु, कुन पंचायत भूमि —— हेतु) अर्थात् कुल 0.156 हेतु वन भूमि का ना. एस. एन. ईल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठलानी द्वारा दिनांक 30/12/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ठलानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि (BSNL) 0.144 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेतु 30/12/21/2021
ग्राम सचिव विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - डॉ. विकास अधिकारी
विधा. - विकास अधिकारी
जनपद - दहरादून



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 30/12/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दलाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम
1.	Suril Singh
2.	Manjul Singh
3.	Babu Singh
4.	Tau Singh
5.	Gagan Singh
6.	Gittam Singh
7.	Sachin Handwal
8.	Tikam Singh
9.	Samu Singh
10.	DR. Tumad Singh

हस्ताक्षर

for
Mr.
Babu
Jaysen
Gagan
Gittam
Tikam
Samu
DR. Tumad

